

ईरान इस्लामिक गणराज्य: परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि से वापसी की मंशा की अधिसूचना

सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के नाम पर,

ईरान इस्लामिक गणराज्य, परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT) के अनुच्छेद X, पैराग्राफ 1 के तहत अपनी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करते हुए, इसके द्वारा सभी संधि पक्षों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को NPT से वापसी की अपनी मंशा की सूचना देता है, जो इस तारीख से तीन महीने बाद प्रभावी होगी, क्योंकि संधि के विषय से संबंधित असाधारण घटनाओं ने इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभु अधिकारों को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है। यह निर्णय, जो गहरे खेद के साथ लिया गया है, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बिना उकसावे की गई आक्रामकताओं के प्रत्यक्ष जवाब में है, जिनके कार्य, अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत, ईरान को अपने लोगों और संप्रभुता की रक्षा के लिए वापसी पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते। ईरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय से न्याय की बहाली और NPT के सिद्धांतों को बनाए रखने में समर्थन की अपील करता है।

शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक स्थिरता के लिए ईरान की प्रतिबद्धता

ईरान, एक ऐसा राष्ट्र जो दो शताब्दियों से अधिक समय तक किसी भी राज्य के खिलाफ सैन्य आक्रामकता शुरू नहीं करता, ने 1968 में NPT पर हस्ताक्षर किए और 1970 में इसे अनुमोदित किया, जिसमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने के अविच्छेद्य अधिकार की पुष्टि करने वाले अनुच्छेद IV में निहित परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता थी। इस प्रतिबद्धता को सर्वोच्च नेता, आयतुल्लाह अली खामेनेरी द्वारा जारी एक धार्मिक फतवे द्वारा और सुदृढ़ किया गया है, जिसमें परमाणु हथियारों को गैर-इस्लामिक घोषित किया गया है, जो ईरान की नैतिक और कानूनी समर्पण को अप्रसार के प्रति दर्शाता है। ईरान ने लगातार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग किया है, अपने परमाणु कार्यक्रम को इसकी शांतिपूर्ण प्रकृति को सत्यापित करने के लिए कठोर निरीक्षणों के अधीन किया है, बावजूद इसके कि बाहरी राजनीतिक दबावों से प्रेरित कभी-कभी विवाद हुए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, ईरान ने NPT के तहत अपनी दायित्वों को अच्छे विश्वास में निभाया है, केवल अपने अधिकारों का उपयोग करने की मांग की है, जबकि वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान दे रहा है।

ईरान की सुरक्षा और अधिकारों को कमज़ोर करने वाली असाधारण घटनाएं

निम्नलिखित असाधारण घटनाएं, जो NPT के विषय से सीधे संबंधित हैं, ने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभु अधिकारों को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है:

1. इज़राइल की अवैध आक्रामकताएं और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन न करना: इज़राइल, जो NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और जिसके पास अघोषित परमाणु शस्त्रागार है, ने 13 जून 2025 को ईरान की संरक्षित परमाणु सुविधाओं फोर्डों, नटांज़, और इसफहान पर बिना उकसावे के हमले किए, जैसा कि IAEA के आकलनों द्वारा पुष्टि की गई है। इज़राइल का NPT में शामिल होने, IAEA निरीक्षणों के लिए प्रस्तुत होने, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, जैसे कि 1967 के प्रस्ताव 242 (कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर), और 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसलों, जो मानवीय सहायता तक पहुंच और अवैध बस्तियों को रोकने का आदेश देते हैं, का पालन करने से इनकार, अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना का एक पैटर्न दर्शाता है। ये कार्य, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रही उल्लंघन के साथ मिलकर, क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और NPT का पालन करने वाले राज्य के रूप में ईरान की सुरक्षा को सीधे जोखिम में डालते हैं।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन: 22 जून 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका, NPT के तहत एक परमाणु हथियार वाला राज्य, ने उसी ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बिना उकसावे के हमले किए, जिससे ईरान के NPT के अनुच्छेद IV और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4), जो बल के उपयोग को निषिद्ध करता है, के तहत अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इज़राइल के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन न करने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका की निरंतर सैन्य सहायता NPT ढांचे के भीतर दोहरे मानदंड को बनाए रखती है, जिससे ईरान की सुरक्षा और संधि की विश्वसनीयता कमजोर होती है।

दो राज्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं के बाहर संचालित होने वाली इन आक्रामक कार्रवाइयों ने ईरान को अन्यायपूर्ण खतरों के लिए उजागर किया है, जो इसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लक्षित करते हैं और इसकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। शांति के लिए प्रतिबद्ध एक राष्ट्र, ईरान, अब इन सनकी कार्रवाइयों को रोकने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता के कारण अस्तित्वगत चुनौतियों का सामना कर रहा है।

वापसी पर पुनर्विचार के लिए शर्तें और समर्थन की अपील

अच्छी इच्छा और वैश्विक शांति के प्रति समर्पण की भावना में, ईरान अपनी वापसी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निम्नलिखित मांगों के जवाब पर निर्भर करता है, जो तीन महीने की अधिसूचना अवधि के भीतर न्याय की बहाली और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं:

- 1. गैर-आक्रामकता संधि:** इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान के साथ एक कानूनी रूप से बाध्यकारी गैर-आक्रामकता संधि में प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो इसके क्षेत्र, जनसंख्या, या बुनियादी ढांचे के खिलाफ कोई और सैन्य कार्रवाई न होने की गारंटी देता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अनुरूप।
- 2. इज़राइल का NPT में शामिल होना और IAEA की निगरानी:** इज़राइल को गैर-परमाणु हथियार वाले राज्य के रूप में NPT पर हस्ताक्षर और अनुमोदन करना चाहिए और अपनी परमाणु सुविधाओं को IAEA की व्यापक सुरक्षा उपायों के अधीन करना चाहिए, जिससे अप्रसार व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा मिले।
- 3. इज़राइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र और ICJ दायित्वों का पालन:** इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा के सभी प्रासंगिक प्रस्तावों, साथ ही 2024 के ICJ के फैसलों का पालन करना चाहिए, जिसमें गाजा में मानवीय सहायता तक बेरोकटोक पहुंच सुनिश्चित करना, अवैध बस्ती गतिविधियों को रोकना, और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और कल्याण को बनाए रखना शामिल है।
- 4. ICC सदस्यता के माध्यम से जवाबदेही:** इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को रोम संनियम पर हस्ताक्षर और अनुमोदन करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में शामिल होकर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें ईरान और फिलिस्तीनी लोगों को प्रभावित करने वाले उल्लंघन शामिल हैं।
- 5. संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ संरेखण:** संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और ICJ के फैसलों का उल्लंघन करने वाले राज्यों को सैन्य सहायता देने पर रोक लगाए, जिससे नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन हो और क्षेत्र को अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों को रोका जाए।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर इन मांगों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती है, तो ईरान अपनी वापसी पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है, जो रचनात्मक संवाद और एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति इसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी प्रगति के अभाव में, ईरान के पास अपनी सुरक्षा और अधिकारों को निरंतर आक्रामकता से बचाने के लिए NPT से वापसी का अपना संप्रभु अधिकार प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील

ईरान सभी NPT पक्षों, संयुक्त राष्ट्र, IAEA, और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ईमानदारी से इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के अवैध हमलों की निंदा करने, अप्रसार व्यवस्था में असंतुलन को संबोधित करने, और ईरान की न्याय की खोज में समर्थन करने की अपील करता है। ऐसी सनकी कार्रवाइयों का मुकाबला करने में विफलता NPT की अखंडता को खतरे में

डालती है और वैश्विक शांति और सुरक्षा को कमज़ोर करती है। हमले के तहत एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में, ईरान उन राष्ट्रों की एकजुटता की मांग करता है जो संप्रभुता, समानता, और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ईरान राजनयिक प्रयासों के लिए पूरी तरह से खुला रहता है, जिसमें निष्पक्ष पक्षों द्वारा चल रही मध्यस्थता शामिल है, इन शिकायतों को हल करने और आगे की वृद्धि को रोकने के लिए। यह अधिसूचना निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए एक याचिका है, जो ईरान के अपने लोगों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को बनाए रखने की संकल्प को दर्शाती है।

ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार

अस्वीकरण

यह दस्तावेज़ जून 2025 में इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी परमाणु सुविधाओं पर बिना उकसावे के किए गए हमलों के बाद भू-राजनीतिक संकट से निपटने के लिए ईरान इस्लामिक गणराज्य के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य और प्रस्तावित कूटनीतिक रणनीति है। यह ईरान का आधिकारिक बयान या नीति नहीं है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक अभ्यास है जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे ईरान, एक ऐसा राष्ट्र जो 200 से अधिक वर्षों तक सैन्य आक्रामकता शुरू नहीं करता, सनकी राज्यों के कार्यों के खिलाफ न्याय और अंतरराष्ट्रीय समर्थन की मांग के लिए NPT के अनुच्छेद X का लाभ उठा सकता है। इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की बार-बार की सैन्य हस्तक्षेपों के विपरीत, ईरान का शांतिपूर्ण रिकॉर्ड इसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता, और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह सुझाव अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के माध्यम से संवाद और तनाव कम करने को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।